इत्यादि के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जा रही चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त हो सकते हैं ।

**देश में बेरोजगारी**

697.**प्रो.रामबख्श सिंह वर्मा**:

**श्रीमती मामती शर्मा**:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर,1998 की स्थिति के अनुसार देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी हैं,

(ख) क्या यह सच है कि प्रतिवर्ष बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही हैं,

(ग) यदि हां,तो बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं,और

(घ) उसके परिणामस्वरूप कितने प्रतिशत तक बेरोजगारी की समस्या का हल होने की संभावना हैं?

**श्रम मंत्री** (**डा.सत्यनारायण जटिया**): (क) और(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा आयोजित नवीनतम श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 1987-88 के दौरान 12 मिलियन बेरोजगारी सामान्य मुख्य स्तर (यूपीएस) (नवीनतम उपलब्ध) के अनुसार 1993-94 के दौरान घट कर 9 मिलियन रह गई हैं ।

(ग) और (घ) नौवीं योजना दृष्टिकोण में पर्याप्त उत्पादक रोजगार व गरीबी उन्मूलन को ध्यान में रखकर कृषि तथा ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की परिकल्पना की गई है । बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार की उच्च दर वाले क्षेत्रों में सैक्टरों,सब-सैक्टरों तथा श्रम सघन प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केन्द्रित करने से विकास प्रक्रिया में स्वत: ही उच्च उत्पादक रोजगार सृजित होगा ।

अनुमार है कि यदि 2007तक पूर्ण रोजगार प्राप्त करना है तो रोजगार वृद्वि की दर 2.8 प्रतिशत वार्षिक रखनी होगी ।

**Guidelines for Wage Settlement**

698. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI J. CHITHARANIAN:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the new guidelines issued to the Public Sector undertakings by the Department of Public Enterprises that wage settlement should now be for a period of ten years instead of the current practice of five years;

(b) if so, what are the details of the guidelines issued in this regard;

(c) whether the major central trade unions have opposed these guidelines; and

(d) if so, the details thereof and Government's response thereto?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) and (b) Yes, sir. The Justice Mohan Committee has recommended that pay package and perquisites for officers and non-unionised supervisors, should be revised every 10 years instead of 5 years as has been the practice so far. The Government in their guidelines for the policy to be adopted for the Sixth round of wage negotiations in the Public sector enterprises have stated that in the event of the Government accepting the above recommendations, the revision of wages of the workers should be effected once in 10 years in order to ensure uniformity.

(c) No representation has been received so far from any major central trade union opposing recommendation of the Mohan Committee.

(d) Does not arise.

**National wage Structure for Workers in Sugar Industry**

699. SHRl JALALUDIN ANSARI:
SHRI J. CHITHARANIAN:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal to set up a sub committee for deciding the national wage structure for workers in the sugar industry;

(b) if so, the criteria for selecting the members of the said committee, and

(c) the names of the members along with their affiliation, if the committee is already constituted?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) The suggestion to set up a sub committee for deciding the national wage structure for sugar industry was made by some members in the meeting of the tripartite committee on sugar industry which was held on 18.1.99. The Government is yet to take a final decision on setting up such a sub committee.

(b) and (c) Do not arise as the committee has not been constituted.

**बेरोजगारी की घटी हुई दर**

700. **श्री ईश दत्त यादव**:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अधिकारित आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी की दर कम हुई हैं,

(ख) यदि हां,तो इस प्रकार के आकंड़ों के स्रोत क्या हैं;और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

**श्रम मंत्री (डा.सत्यनारायण जटिया)**: (क) और (ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ),नियोजन एंव कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किए गए नवीनतम श्रम बल सर्वक्षण के अनुसार सामान्य प्रमुख स्थिति के अनुसार 1987-88 से 1993-94 तक की पांच वर्षो की अवधि में बेरोजगारी दर में कमी आई हैं। बेरोजगारी दर 1987-88 के दौरान 3.77 प्रतिशत एंव 1993-94 के दौरान 2.56 प्रतिशत थी।

(ग) नौंवी योजना में अल्प रोजगार की उच्च दर,श्रमिकों की बढती नैमित्तिकता एंव गरीब लोगों के लिए रोजगार अवसरों में वृविद्व करने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। अत: नौंवी योजना में राष्ट्रीय रोजगार आश्वासन योजना को कार्यान्वित करने पर बल दिया जाएगा।

**बेरोजगार व्यक्ति**

701. **श्री ईश दत्त यादव**:

**चौधरी हरमोहन सिंह यादव**:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वे कौन-कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से सरकार बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करती हैं,

(ख) वर्तमान में बेरोजगार व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी हैं;और

(ग) बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार की कौन-कौन सी योजनाएं हैं ?

**श्रम मंत्री (डा.सत्यनारायण जटिया)**: (क) देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का अनुमान तैयार करने के लिए सूचना का मुख्य स्रोत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन,नियोजन एंव कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा रोजगार एंव बेरोजगारी पर किया जाने वाला पंचवर्षीय सर्वेक्षण है।

(ख) 1993-94 (एनएसएसओ का 50वां चक्र ) में बेरोजगार व्यक्तियों के अनुमान को दर्शाने वाला विवरण संलग्र हैं।(**नीचे देखिए**)

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में रोजगार उपलब्ध कराने वाले प्रमुख गरीबी उपशमन कार्यक्रम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम,जवाहर योजना एंव रोजगार आश्वासन योजना हैं।

गरीबी उपशमन एंव रोजगार सृजन हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की समीक्षा एंव विश्लेषण पर हाशिम समिति की रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं के परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना शुरू की गई हैं एवं एनआरवाई,पीएमएआईयूपीईपी तथा यूपीएसपी (गरीब लोगों हेतु शहरी बुनियादी सेवाएं ) को चरणबद्व कर दिया गया है। योजना पर 1.12.1997 से कार्य शुरू कर दिया गया है । एसजेएसआरवाई शहरी बेरोजगारों अथवा अल्प रोजगार प्राप्त गरीब लोगों को स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देने एंव मजदूरी नियोजन के माध्यम से उत्पादक रोजगार उपलब्ध कराने पर बल देती हैं।

ग्रामीण एंव शहरी दोनों ही क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना को एक केन्द्रीय प्लान स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा हैं।

**विवरण**

**राज्य-वार बेरोजगारी (यू.पी.एस.)*(000 व्यक्ति)**

| क्र.सं. | राज्य | बेरोजगारी 1993-94 |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 454 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 5 |
| 3. | असम | 590 |